सुलह-समझौते के जरिये देशभर में निपटाए गए 1.14 करोड़ विवाद

लोक अदालत ▶ त्वरित न्याय के लिए वैकल्पिक तंत्र पर बढ़ रहा भरोसा

न्याय तक लोगों की पहुंच सुलभ करने के लिए नालसा की पहल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देशभर में शनिवार को आयोजित लोक अदालतों में सुलह-समझौते के जरिये 1.14 करोड़ विवाद निपटाए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने न्याय तक लोगों की पहुंच सुलभ करने और त्वरित न्याय के लिए शनिवार को वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। देशभर में 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तालुका, जिला और उच्च न्यायालयों में आयोजित इन लोक अदालतों में पक्षकारों के बीच सुलह, समझौते के जरिये विवादों का निपटारा किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न पहलों के माध्यम से सभी के लिए न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए कार्य करता है। इसी क्रम में लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,14,56,529 विवादों का निपटारा किया गया। कुल मामलों में से 94,60,864 मामले प्री-लिटिगेशन के थे। यानी ये विवाद अदालत में विधिवत केस दाखिल होने से पहले ही सुलह समझौते के जरिये निपटा दिए गए। 19,95,665 लंबित केस थे, जिनका निपटारा लोक अदालतों में हुआ है। निपटाए गए केसों में ट्रैफिक चालान, राजस्व मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़ कर), भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता मामले और अन्य दीवानी मामले शामिल थे। शनिवार शाम 6.30 बजे तक देशभर से प्राप्त ब्योरे के अनुसार, इन मामलों में कुल निपटान राशि लगभग 8,482.08 करोड़ रुपये की रही। कुछ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

लंबित मुकदमों का बोझ कम करने में मददगार।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए विवादों की संख्या और लोक अदालतों की सफलता दर्शाती है कि लोक अदालतों में लोगों का भरोसा है। लोग वैकल्पिक तरीकों से आपसी सुलह और मध्यस्थता के जरिये विवाद सुलझाने के इच्छुक हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार देशभर में लोक अदालतों के आयोजन और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने में लगा रहता है। इससे न सिर्फ लंबित मुकदमों का बोझ कम होता है, बल्कि त्वरित न्याय भी सुनिश्चित होता है।

अंतरिक्ष में फंसीं सुनीता विलियम्स वहीं से राष्ट्रपति चुनाव में करेंगी मतदान

बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष स्टेशन गईं सुनीता जून से ही वहीं फंसी हैं

अमेरिका में पांच नवंबर को चुनाव, अगले वर्ष की शुरुआत में धरती पर लौटेंगी

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका में पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट प्रत्याशियों के बीच घमासान जारी है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) में जून से फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतवंशी सुनीता विलियम्स भी पांच नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वहीं से मतदान की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के अगले वर्ष की शुरुआत में धरती पर लौटने की संभावना है।

सुनीता विलियम्स ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एक नागरिक के रूप में मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। विल्मोर ने कहा कि मैंने मतपत्र के लिए अनुरोध भी भेज दिया है। जून में स्टारलाइनर के अंतरिक्ष यान से आइएसएस गए नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री यान में कुछ समस्याओं के कारण उससे वापस नहीं लौटे। पिछले सप्ताह स्टारलाइनर धरती पर लौट आया है। न्यूयार्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नासा की अंतरिक्ष यात्री केट रुबिंस ने भी 2020 में अंतरिक्ष से वोट किया था। अंतरिक्ष यात्री 1997 से ही अंतरिक्ष से मतदान कर रहे हैं। टेक्सास की विधायिका ने बिल पास कर नासा कर्मचारियों को अंतरिक्ष से मत देने का अधिकार दे दिया था।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) से एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्मोर। एएफपी

हैरिस ने नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का किया आह्वान

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह राष्ट्रपति जो बाइडन से अलग हैं, क्योंकि वह नई पीढ़ी का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने अमेरिकियों से बदलाव की अपील करते हुए कहा, वह नई पीढ़ी को नेतृत्व का मौका दें। वहीं, रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने फिलाडेल्फिया बहस की चर्चा करते हुए कहा, उन्होंने पूछे गए सभी सवालों का जवाब अच्छे से दिया था। यदि उनका मूड अच्छा रहा तो वह हैरिस से दोबारा बहस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफार्म के शेयरों को बेचने से इन्कार किया है।

चुनावी अभियान के लिए पेंसिल्वेनिया के जोंस्टाउन पहुंचने के बाद समर्थकों से मिलने के दौरान सीनेटर जान फेटरमैन तथा उनकी पत्नी के साथ सेल्फी खिंचवाती कमला हैरिस (मध्य में)। एपी

पहले क्वाड फिर अगले महीने ब्रिक्स में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 21 सितंबर को अमेरिका में होगी क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक
- पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने रूस भी जाएंगे

किसी भी गुट में न रहते हुए अपने राष्ट्र हितों के मुताबिक कूटनीति की भारत सरकार की नीति और रफ्तार पकड़ेगी। इस क्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते 21 सितंबर को क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत क्वाड के सदस्य हैं। इस बार अमेरिका में होने वाली इस बैठक में मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, आस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अलबनिजी और जापान के पीएम किशिदा फुमियो हिस्सा लेंगे।

अक्टूबर में मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन सरीखे नेताओं के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक सम्मेलन होगा। ऐसे समय में जब अमेरिका की अगुआई में पश्चिमी देश यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर रूस व चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं, भारत रूस-चीन संग मिलकर ब्रिक्स की भावी नीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

अमेरिका व आस्ट्रेलिया ने संकेत दिया कि इस बार क्वाड की बैठक बड़े एजेंडे पर होगी। बाइडन-हैरिस प्रशासन ने क्वाड को शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। क्वाड की पहली बैठक 2021 में व्हाइट हाउस में हुई थी। वैसे इस साल यह बैठक भारत में होनी थी, पर कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। अब अगले वर्ष यह बैठक भारत में होगी।

क्वाड की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में चारों देशों के विदेश मंत्रालयों के स्तर पर बैठक हुई। आस्ट्रेलिया ने कहा, हालिया वर्षों में क्वाड के विदेश मंत्रियों के बीच आठ बैठकें हुई हैं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर सही तरीके से काम कर रहा है। इसके सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां सभी की संप्रभुता का आदर किया जाए।

सब्सिडी और रेवड़ी के बोझ से राज्यों पर बढ़ता वित्तीय दबाव

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली : मुफ्त व सब्सिडी वाली बिजली का वादा कर सत्ता में आने वाली हिमाचल की सरकार अब बिजली की सब्सिडी में कटौती करने जा रही है तो उधर पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह ही राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दोनों ही राज्यों की इन दिनों वित्तीय सेहत ज्यादा खराब चल रही है और वे अपने-अपने कर्मचारियों को वेतन व पेंशन तक देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के समय पर भुगतान को केंद्र से मदद मांगी है। ऐसी ही नौबत उन राज्यों के साथ आ सकती है जहां सत्ता में आने के लिए रेवड़ियां बांटने का वादा किया और इससे उनकी सब्सिडी का बिल बढ़ता जा रहा है।

चुनाव के दौरान बिजली सब्सिडी, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर, किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं-युवतियों को बिना किसी काम के महीने का नकद भत्ता, मुफ्त लैपटाप, युवाओं को बिना काम के भत्ता जैसे वादे और फिर इन्हें पूरा करने की कसरत में राज्यों का वित्तीय भार व कर्ज बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह हो रहा कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर औद्योगिकीकरण जैसे कार्यों पर कई राज्य कम खर्च कर रहे हैं। ऐसे में औद्योगिक निवेश प्रभावित होगा और रोजगार सृजन में भी कमी आएगी।

आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विकास या बुनियादी सुविधा के मद में कम खर्च करने वाले राज्य पिछड़ते चले जाएंगे और इसकी कीमत वहां अगली पीढ़ी चुकाएगी। राजस्व की कमी से उन राज्यों में शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, इनेवेशन, संपदा निर्माण जैसे चीजें भी प्रभावित होंगी। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआइपीएफपी) के अर्थशास्त्री पिनाकी चक्रवर्ती कहते हैं कि राज्यों की वित्तीय सेहत में खराबी को गहराई से देखने की जरूरत है। कोरोनाकाल में राज्यों की वित्तीय हालत बहुत ही खराब हो गई। जहां तक इसका सवाल है कि कितना रेवेन्यू खर्च होना चाहिए और कितना कैपिटल खर्च (विकास के मद में) होना चाहिए तो इसके लिए केंद्र की तरफ से प्लानिंग की जरूरत है। हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों का संकट नकदी प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट क्राइसिस) से जुड़ा है। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट की वजह से राज्य एक सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकते हैं। राज्यों के उधार लेने की सीमा केंद्र सरकार तय करती है। ऐसे में राज्य कई बार उधार लेकर अनुमानित राजस्व के घाटे को पूर्ति नहीं कर पाते हैं और फिर वे अपने खर्च में कटौती करते हैं।

देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं और इनकी वित्तीय हालत भी कमोबेश प्रभावित हो रही है। लेकिन बजट आकार बड़ा होने और औद्योगिक विकास, निर्यात व अन्य सर्विस सेक्टर में आगे निकलने के कारण इनको अपने राजस्व खर्च पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है हर साल राज्यों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,87,432 करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च किए। वित्त वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में सब्सिडी का यह खर्च बढ़कर 4,19,418 करोड़ हो गया।

राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो भी रही है तो सैलरी, पेंशन व कर्ज ब्याज पर होने वाले खर्च (रेवेन्यू खर्च) भी लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों का राजस्व खर्च ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) का औसतन 13.7 %था जो 2023-24 में बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गया।

खजाने की कीमत पर...

- पांच साल में सब्सिडी बोझ दोगुने से अधिक, इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य विकास कार्यक्रम हो रहे हैं प्रभावित
- औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में पिछड़ सकते हैं अधिक वित्तीय घाटे वाले राज्य
- सब्सिडी और रेवड़ी की वजह से देश के सभी राज्यों का औसतन रेवेन्यू खर्च उनके कुल खर्च का 82 प्रतिशत
- हिमाचल और पंजाब सरकार की वित्तीय सेहत बेहद खस्ता, रेवड़ियां बांटने का वादा कर हासिल की थी सत्ता

मार्च 2023 तक राज्यों पर बकाया उनके जीएसडीपी में

आंध्र प्रदेश	33%
बिहार	39%
छत्तीसगढ़	27%
दिल्ली	2%
गुजरात	20%
हिमाचल प्रदेश	42%
पंजाब	48%
मध्य प्रदेश	29%
उत्तराखंड	32%
उत्तर प्रदेश	33%
पश्चिम बंगाल	36%
जम्मू-कश्मीर	33%
हरियाणा	29%
झारखंड	34%

राज्यों का राजकोषीय घाटा

(वित्त वर्ष 2023-24 के जीडीपी % में)

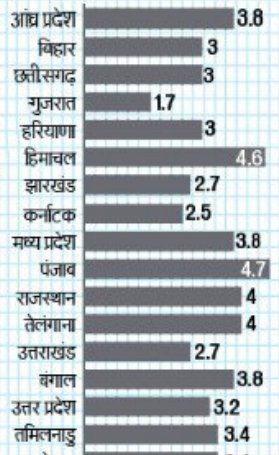

राज्यों की तरफ से कैपिटल खर्च

जीएसडीपी का (2019-24 का औसत)

महाराष्ट्र	1.5%
तमिलनाडु	1.6 %
गुजरात	1.7 %
उत्तर प्रदेश	3.8 %
हरियाणा	1.5 %
तेलंगाना	2.7 %
आंध्र प्रदेश	1.5%
केरल	1.4 %
बिहार	3.5 %
झारखंड	3.8 %
छत्तीसगढ़	2.8 %
मध्य प्रदेश	3.6 %
पंजाब	1.2 %
हिमाचल	3.1 %
उत्तराखंड	2.7%

राज्यों की रेवेन्यू प्राप्ति और रेवेन्यू खर्च

2023-24 (बजट अनुमान) करोड़ रुपये में

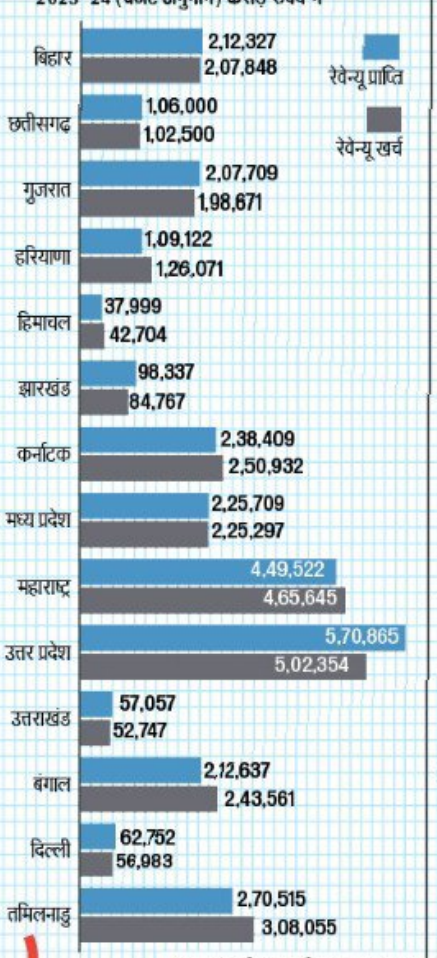

(स्रोत: आरबीआइ व पीआरएस इंडिया)

राज्यों में दी जाने वाली सब्सिडी

(करोड़ रुपये में)

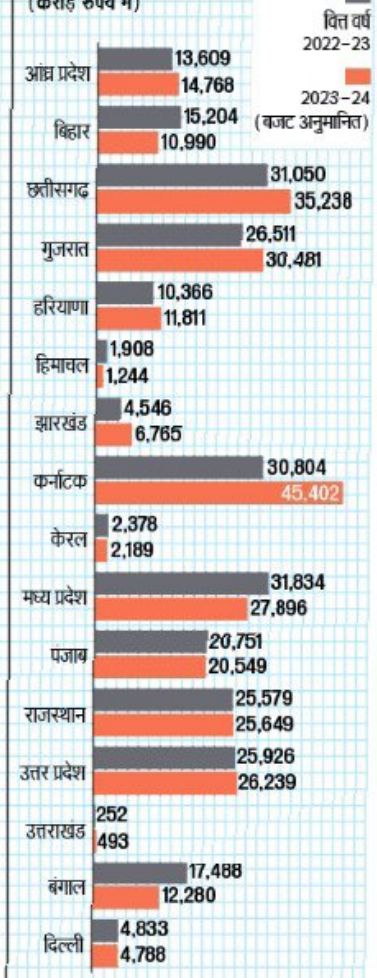

आरबीआई की रिपोर्ट गरीब राज्यों में निवेश कम, अमीर और अमीर हो रहे

12 साल में ओडिशा में 'संपन्नता' 104% बढ़ी तो बिहार में 47% ही

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश में निवेश भले ही लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन यह सिर्फ बड़े राज्यों में ही हो रहा है। इन राज्यों में संपन्नता बढ़ रही है, जबकि बीमारू राज्य और गरीब हो रहे हैं।

देश की अर्थव्यवस्था पर बनी भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट बताती है कि गरीब राज्यों में ओडिशा के हालात सबसे तेजी से सुधरे हैं। यहां बीते 12 साल में प्रति व्यक्ति जीडीपी 104% बढ़कर 98 हजार रुपए हो गई है। क्रिसिल के अर्थशास्त्री डीके जोशी कहते हैं कि प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य उत्पादन। यह बताती है कि राज्य में संपन्नता का स्तर कितना है। ग्रोथ या निवेश उन्हीं राज्यों में ज्यादा जा रहा है, जो पहले से बहुत अमीर हैं। इस मामले में ओडिशा ने हालात तेजी से सुधारे हैं। वहीं, बिहार आज भी 12 साल पुरानी स्थिति में है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ 47% ही बढ़ी है जो देश में सबसे कम है। 18 बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे अमीर है। हरियाणा दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट बताती है कि देश में औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी 2023-24 में 1.06 लाख रही।

ग्रोथ... उप्र में बेहतर नहीं, बिहार के पहले पंजाब का नंबर

रिपोर्ट बताती है कि उप्र और पंजाब में भी आर्थिक हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। 2011-12 से 2023-24 में उप्र में प्रति व्यक्ति जीडीपी 56% बढ़कर सिर्फ 50 हजार रु. तक ही पहुंची है। पंजाब की 1.30 लाख रु. जरूर है, लेकिन 12 साल में इसे सिर्फ 52% की ही बढ़त है। यह बिहार के बाद सबसे कम है। 13 छोटे-बड़े राज्य ऐसे हैं, जिनकी सालाना प्रति व्यक्ति जीडीपी आज भी एक लाख रु. से कम है। यह औसत से भी कम है। इन्हीं 12 साल में ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात की प्रति व्यक्ति जीडीपी दोगुनी हुई है।

प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी बढ़ी...

राज्य	2023-24	2011-12	वृद्धि
हरियाणा	1.85 लाख	1.06 लाख	74.5%
गुजरात	1.81 लाख	87 हजार	108%
महाराष्ट्र	1.63 लाख	99 हजार	64.5%
पंजाब	1.30 लाख	85 हजार	52.9%
ओडिशा	98 हजार	48 हजार	104%
छत्तीसगढ़	92 हजार	55 हजार	67.2%
राजस्थान	91 हजार	57 हजार	59.3%
मध्य प्रदेश	66 हजार	38 हजार	73.6%

टॉप 5 राज्य, जहां सबसे ज्यादा

कर्नाटक	1.86
हरियाणा	1.85
तेलंगाना	1.83
तमिलनाडु	1.79
महाराष्ट्र	1.63

टॉप-5 राज्य, जहां सबसे कम जीडीपी

बिहार	0.32
उत्तर प्रदेश	0.50
झारखंड	0.65
मध्य प्रदेश	0.66
बंगाल	0.79

- छोटे राज्यों में सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय 2.92 लाख रुपए है। यह देश में सर्वाधिक है। दिल्ली (2.73 लाख) दूसरे स्थान पर है।

मप्र-महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां प्री कोविड लेवल से भी नीचे

रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश उन राज्यों में है जहां मैन्युफैक्चरिंग का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान (वैल्यू एडिशन) बढ़ने के बजाय घट गया है। 2023-24 में इस सेक्टर का वैल्यू एडिशन 52.64 हजार करोड़ रहा, जो 2018-19 में 61.33 हजार करोड़ का था। महाराष्ट्र में 18-19 में यह 3.26 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2021-22 में घटकर 2.87 लाख करोड़ का रहा गया। यानी 15.38% की गिरावट आई।

बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो का हुआ समापन

गंगा की 11 सहायक नदियों में 1 करोड़ मछलियां छोड़ी जाएंगी

पटना| पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने कहा कि मत्स्य उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर के साथ-साथ निर्यातक हो गया है। 38 हजार मीट्रिक टन मछली पड़ोस के राज्यों में निर्यात की जा रही है। बिहार के 56,607 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया है। रेणु देवी ने बताया कि नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत गंगा की 11 सहायक नदियों में एक करोड़ मछलियां छोड़ी जाएंगी। वे शनिवार को बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुर्गीपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल से तरक्की होगी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में किसान तकनीक के साथ आगे बढ़ेंगे तो तरक्की होगी। एक्सपो को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से माहौल और वातावरण बनता है। किसानों और इस क्षेत्र में लगी कंपनियां अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की संभावना तलाशती हैं। कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुपालन और मत्स्य पालन का योगदान 20 प्रतिशत है। मछलीपालन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार में पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में 116 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 260 और मछली उत्पादन में 193 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

ढाई फीट गहरे पानी में भी मछली पालन हो रहा

कृषि मंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से ढाई फीट गहरे पानी में भी मछली पालन हो रहा है। विभाग की प्रधान सचिव डॉ एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य में मौजूद 9 लाख हेक्टेयर चौर क्षेत्र में 10-20 हजार हेक्टेयर चौर क्षेत्र को विकसित करने से मछली उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है। मौके पर आइसकंटेनर युक्त 25 साइकिल का वितरण किया। मछलियों की बिक्री में इनका इस्तेमाल होगा।

{ THIRD EYE }

Barkha Dutt

Failure of political astuteness in West Bengal, Manipur

Often, the most obvious response to the crises such those in the two states is the appropriate one. It is resistance to the obvious that muddies the waters

The image of West Bengal chief minister (CM) Mamata Banerjee facing a row of empty white chairs, dressed up with blue bows, "waiting and waiting and waiting" for doctors to show up, is an intriguing one, especially when it was followed by the embattled CM folding hands and apologising for the failure to break the impasse with protesting doctors, capping it off with a dramatic and emotional "ready to resign' gambit.

Of course, the irony of the moment is lost on no one. These comments by the Trinamool Congress chief were live-streamed. And that was the precise issue over which the talks broke down before they could start.

The doctors — agitating for a month over the rape and murder of a young doctor at a government medical college and a series of missteps and attempted cover-ups that evidently followed — had made live-streaming the meeting with the CM a pre-condition. They have remained adamant on this demand, arguing that if the Supreme Court can live-stream the case, there is no reason for the West Bengal government to be diffident. The offer of recording the proceedings and releasing them with a Supreme Court go-ahead has not been accepted by the doctors so far.

In this zero-sum game, one has to see who blinks first. But one can't help but wonder why Banerjee simply did not do what she did this week, right at the beginning of the protests. The folded hands, the mellow tone, the apology for not being able to break the stalemate, the emphasis on her waiting for over two hours for doctors — perhaps had this been the approach in the hours and days after the crime, there would have been no crisis to handle. For a politician born and shaped by agitations, it is surprising that the CM showed a remarkable lack of instinct. Even her revelation that the Kolkata police chief had offered to resign, but it was she who turned it down because of the impending festival season, was bewildering. As one young doctor said to me, "Who is thinking of festivities right now?"

While the Bharatiya Janata Party (BJP) may be on the front foot in the state in its criticism of the CM, similar questions about a perplexing lack of instinct should be redirected to the party leadership when it comes to Manipur.

Again, to be clear, I am not at all drawing any literal comparisons between a state where more than 200 people have been killed in violent ethnic clashes since May 2023 and the RG Kar case in West Bengal. The similarity is confined to how politicians respond in times of crisis, big and small. And how common sense seems to betray them when it is most needed.

ONE CAN'T HELP BUT WONDER WHY BANERJEE DID NOT DO WHAT SHE DID THIS WEEK, RIGHT AT THE BEGINNING OF THE PROTESTS. THOUGH SHAPED BY AGITATIONS, SHE SHOWED A REMARKABLE LACK OF INSTINCT

In Manipur, the BJP's stubborn refusal to remove N Biren Singh as CM is inexplicable. Political party lines have collapsed in Manipur. Of the ten legislators who have asked for the CM to be prosecuted for his role in the strife, seven are from the BJP REUTERS

In Manipur, the BJP's stubborn refusal to remove N Biren Singh as CM is inexplicable. The situation in the state is so alarming that many have likened it to a civil war, where members of the Meitei and Kuki communities can no longer cross over into geographies dominated by the other. A former soldier of the Army was killed this week just because he accidentally crossed the "buffer zone" that separates the ethnic groups. Women are among 11 people killed since the beginning of this month. Thousands of weapons are in the hands of civilians in both communities, farmers and students.

Keyboard nationalists who otherwise run patriotism tests on everyone else and don't hesitate to label people as anti-national for the slightest dissent seem entirely unmoved at the situation. When former soldier Havaldar Limkholal Mate's wife said, as she did to me, that her husband "fought for India, but was killed like an animal," where are all the self-appointed arbiters of nationalism? Political party lines have collapsed in Manipur. Of the ten legislators who have asked for the CM to be prosecuted for his role in the strife, seven are from the BJP. I can understand political continuity when the violence is external, for instance, during insurgencies or wartime. But this is a state at war with itself. This is a failure of law and order, yes, but it is, above all, a failure of politics. Removing Singh also affords a chance to bring the clashing parties to the dialogue table, besides being the obviously correct thing to do.

From West Bengal to Manipur, often, the most obvious response is the appropriate one. It is resistance to the obvious that muddies the waters — sometimes, beyond repair.

Barkha Dutt is an award-winning journalist and author. The views expressed are personal

US to consider more funding to spur India's clean energy sector

Bloomberg

feedback@livemint.com

The lender has offered financing worth almost $4 billion in India, making the nation its largest single market ISTOCKPHOTO

The US International Development Finance Corp. will consider more deals to accelerate India's adoption of clean energy after making loans to solar equipment makers.

Recent agreements included a $500 million loan to a First Solar Inc. manufacturing facility in Tamil Nadu, and the lender has struck previous pacts with Tata Power Renewable Energy Ltd. and Vikram Solar Ltd. "We see scope for expanding that," Nisha Biswal, deputy CEO of the US government agency, said in an interview. "One of the key conversations we are going to have is clean energy manufacturing," including solar, wind, cooling and the electric vehicle value chain, she said. The lender has offered financing worth almost $4 billion in India, making the nation its largest single market.

India, the world's third-largest emitter, needs trillions of dollars in investment in clean energy generation, grid upgrades and EVs to meet targets to decarbonize, according to BloombergNEF. Prime Minister Narendra Modi has pledged to hit net zero by 2070, and is also contending with fast rising electricity demand in the world's most-populous nation.

"No global target is achievable if India doesn't achieve its target," Biswal said.

Post-glacial ecosystems could help to slow down climate change, says decade-long study

Vikas Vasudeva
CHANDIGARH

The retreat of glaciers may be one of the most evident signs of climate change, but it will leave behind new ecosystems that can help mitigate climate change, says a global study titled "The development of terrestrial ecosystems emerging after glacier retreat".

The study involved collecting more than 1,200 soil samples from nearly fifty glaciers worldwide. AP

The study, published in the multidisciplinary science journal *Nature*, suggests that deglaciation may accelerate climate change by reducing surface reflectivity and releasing stored carbon, but the post-glacial ecosystems could help slow it down. The study, led by professor Gentile Francesco Ficetola from the University of Milan and Silvio Marta from Italy's Institute of Geosciences and Earth Resources, is the result of a decade-long investigation into how ecosystems develop in glacial retreat areas. Their findings show how ecosystems develop in these areas and suggest that proper management could boost biogeochemical processes, aiding in climate change mitigation.

1,200 samples analysed

The study involved collecting more than 1,200 soil samples from nearly fifty glaciers worldwide. Dr. Pritam Chand of Central University, Punjab, along with Professor Milap Chand Sharma of Jawaharlal Nehru University, Delhi, contributed to this study by analysing samples from the Gangotri and Bara Shigri glaciers in the Indian Himalayas.

Pointing out that immediately after glacier retreat microorganisms such as bacteria, protists and algae are the first to colonise the barren landscape, making minerals available for other species, Mr. Pritam Chand said that within a decade, hardy plants such as lichens, mosses and grass begin to establish enriching the soil and paving the way for more complex plant life and larger animals. "With proper management, these areas can develop rapidly, providing temporary habitats for species threatened by climate change," he told *The Hindu*.

SC grants bail, Kejriwal walks free

Bench reinforces conditions from July 12 order granting bail in a related money laundering case; Justice Bhuyan writes separate opinion, questioning the timing and necessity of arrest, asking the CBI to dispel the notion of being a caged parrot

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday ordered Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to be released on regular bail in a case registered by the Central Bureau of Investigation (CBI) in relation to the now-scrapped excise policy.

Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan concurred to grant bail to Mr. Kejriwal but differed on the point of the legality of his arrest.

Justice Kant barred Mr. Kejriwal from visiting the office of the Chief Minister and the Delhi Secretariat or signing official files unless it was required and necessary for obtaining clearance/approval of the Lieutenant Governor of Delhi. These conditions were adopted from the July 12 order of the apex court granting the Chief Minister bail in a connected money laundering case investigated by the Directorate of Enforcement (ED).

Big win: Arvind Kejriwal being welcomed by Aam Aadmi Party workers and supporters after coming out of Tihar jail on bail, on Friday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Justice Bhuyan said he had "serious reservations" about the two bail conditions but refrained from delving further into them as they were part of the July 12 order in a different case heard by a coordinate Bench of the apex court. His restraint would mean the two bail conditions would now be effective.

The verdict was based on petitions filed by Mr. Kejriwal, seeking bail and the quashing of his arrest by the CBI on June 26. Later in the day, he stepped out of Tihar jail to a resounding welcome by AAP leaders and supporters.

While Justice Kant said the CBI arrest warranted no interference as it did not suffer from any "procedural infirmity", Justice Bhuyan chose to write a separate opinion questioning both its timing and necessity without mincing words. He questioned the urgency shown by the CBI to arrest Mr. Kejriwal 22 months after the registration of the First Information Report in the case.

Noting that the power of arrest must be used sparingly and is not a ruse for harassment, Justice Bhuyan urged the CBI to be above board in its actions like "Caesar's wife" and give the public the perception of an "uncaged parrot".

"In a functional democracy governed by the rule of law, perception matters. Like Caesar's wife, an investigating agency must be above board. Not so long ago, the Supreme Court had castigated the CBI for being a caged parrot. It is imperative that CBI dispel this notion. Rather, the perception should be that of an uncaged parrot," Justice Bhuyan wrote.

CONTINUED ON
» PAGE 8
MORE REPORTS ON
» PAGES 2, 8

Being 'trans' is being human

Kavita Krishnan

a feminist activist and writer

Last year, at a closed door tribunal, I met several very young transpersons from rural and urban working class communities. It was heartbreaking to see teenagers brutalised and evicted by family, surviving suicide attempts as well as persecution and violence on the streets. In the stormy debates on the 'transgender question', their voices remind me of what stakes are real.

This is not about western culture wars, or debates over sex, gender, or sports. It is about the rights of every human being to be recognised and respected as themselves; to never be asked to deny, disguise, or defend their self-hood in order to enjoy civil rights and equality.

Universal today but problems in the past

Principles of human rights that are today established as universal, were once treated as 'questions', 'problems' and 'debates'. The slavery question. The woman question/problem. The (N-word) question/problem. The suffrage question. The segregation question. The untouchability question. The inter-racial/inter-caste marriage question. The age of consent question. The homosexual question/problem. The Jewish question/problem. These are all titles of writings by some of the best-known historical figures in the world, as well as letters to editors. Bathroom segregation was rationalised as necessary to protect white women from predatory black men on the prowl; police raids on bathrooms to arrest gay men were rationalised to keep boys safe. 'Bathroom bills' to keep transwomen from raping women in toilets are following a tired old script.

It was a Nazi member of the International Olympics Committee who proposed a policy that "ladies taking part in the Games 1940 shall produce doctors' certificates stating that they are women" – ironically, such a policy came into effect in 1948, after the Nazi defeat (at the London Games) – "Officials required female Olympians to submit an affidavit, signed by a doctor, certifying that they were women."

What seemed to be legitimate 'questions' back then were in fact designed to deny civil rights. Today, it is only the far-right that seeks to make those questions "great again", and unsurprisingly, it also derides trans rights. But it is 'gender critical' progressive intellectuals and activists who do what the openly bigoted far-right cannot: frame trans rights as a 'question' requiring reasonable debate. This allows trans rights activists to be accused of being an unreasonable mob that cancels critics through bullying and violence. Search the Internet though and one finds out that movements we celebrate today faced the same accusations. Having your realness 'debated' does make one angry. Black people, women, lesbians and gays were known to 'riot', smash windows, disrupt meetings, vandalise property, set buildings on fire, spit at the police and so on.

The gender-critical mantra is that 'biological sex is real'. The corollary is that transgender identity is not real. Gender-critical progressives lobby for laws penalising or prohibiting the acceptance of trans personhood as real (by textbooks, toilets, schools, sports, hospitals). And the far-right works to enact such laws. In 2022-23, Republican members of the U.S. Congress introduced a Bill which, if passed, would prohibit federally-funded libraries and schools from keeping any material with information on sexual orientation, gender identity, or sex education. Predictably, these laws also penalise and prohibit the acceptance of homosexuality as real.

Existence is not an abstract debate

Social scientists cannot be agnostic on the 'question' of trans 'existence' but claim to offer an objective and dispassionate 'explanation' of the 'emergence' of transpersons as a symptom of political philosophy or ideology. 'Emergence' implies that being trans is a trend, here today, gone tomorrow. Existence is not an abstract debate. Human beings can enjoy their rights only if their identity is affirmed as 'real' in law, not 'lifestyle'. To say that trans persons are free to dress as they wish as long as their trans-identity is denied in law is no different from saying people are free to be gay in private, but must not 'flaunt their lifestyle' by demanding the legal right to marry as heterosexuals do.

The openly partisan far-right discourse declares transpersons and non-binary sexualities to be synthetic symptoms of 'gender ideology' just as gender-critical discourse does. But the latter pretends not to notice that the former declares human rights, multiculturalism, the delegitimisation of hierarchies of caste, race and gender; abortion, and homosexuality also to be symptoms of 'liberal elite ideology'.

What is the relationship of sexual identity and gender to mind and body? Is it biologically self-evident that a woman (to quote author and leading gender-critical campaigner J.K. Rowling) is a "human being who belongs to the sex class that produces large gametes (ova)"?

Simone de Beauvoir's understanding was the opposite of Rowling's; her iconic work, *The Second Sex*, begins by questioning the definition of 'woman' as 'a womb, an ovary'. On the next page, she says the male/female binary is not as obvious as it seems: "the very meaning of division of the species into two sexes is not clear".

Her famous line, "One is not born, but rather becomes, a woman" is far more radical than a rejection of the notion that (biological) sex determines (social) gender. In fact, she does not see the sexed body as an abstract fixed 'reality' that is interpreted by the 'mind' as 'gender'. Our consciousness of the body is inseparable from the way we experience it in our social life: "the body is not a thing, it is a situation: it is our grasp on the world and the outline for our projects". The body (sex) does not determine the shape of gendered consciousness; but gendered consciousness too is not tied to a specific anatomical form. That is, "a consciousness without a body is inconceivable", but "this body need not possess this or that particular structure".

The Second Sex challenged the long-held status of the male/female sex binary as 'universal truth', and in doing so, built on the work of other philosophers who had challenged the Cartesian mind/body binary. The so-called 'culture wars' must not be dignified as a product of a uniquely bewildering disruption by transgenders of male/female, mind/body binaries. They are a garden variety reactionary backlash, seen every time a hitherto dehumanised and discriminated people forced the world to acknowledge their identity as entitled to the same dignity and civil liberties as those more privileged.

The issue of society's character

Science fiction can sometimes clarify contemporary conflicts by placing them in 'space', outside the context of our own inherited prejudices. In an episode in *Star Trek: The Next Generation* ("The Measure of a Man") a judicial trial is held to decide if Data, an android and a beloved member of the crew, is the property of Star Fleet and can be dismantled for research against his will. A devastating demonstration argues that Data is not human, since a human being can dismember his limbs and shut down his body. In response, Captain Picard forces the court to look at Data as he sees himself: asserting his "right to choose", and his "rights and status" as a "person" rather than "property". What is on trial is the measure of humanity's character, not the measure of Data's personhood based on an examination of his parts. As Picard puts it: the verdict "will reveal the kind of a people we are", and "could significantly redefine the boundaries of personal liberty and freedom, expanding them for some, savagely curtailing them for others". It is our society's character, not the sexual and gender identity of transpersons, that is under 'question'. Black bodies (especially their private parts) were once studied with the same air of scientific detachment as trans and intersex bodies are today, to assess the extent to which they were 'real' humans.

It is trans-sceptics, not transpersons, who are fragmenting the integral human self.

To 'be' trans or gay is to 'be' human; to study their parts to determine their 'realness' is always already a dehumanising exercise.

It is 'trans-sceptics' who are fragmenting the integral human self